राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

लखनऊ, बुधवार, 18 जुलाई 2025
वर्ष 16, अंक 80, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

महा खुलासा; फर्जी बरसात के विवाद में फिर फंसे लेखपाल भूपेंद्र वर्मा...03

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए देश के सात मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना ...04

एक्साइज पॉलिसी केसः जज बदलने की अपील... हाईकोर्ट से इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

● दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने SC में याचिका दायर कर जज बदलने की मांग की है।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से इनकार के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जज बदलने की मांग की है. केजरीवाल ने याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने की अपील की है. केजरीवाल के साथ-साथ सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा है कि सीबीआई की याचिका मौजूदा रोस्टर के हिसाब से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को दी गई है. उन्होंने कहा कि केस से अलग होने की किसी भी रिक्वेस्ट पर संबंधित जज को ही विचार करना होगा. कोर्ट ने कहा कि हालांकि, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ऑर्डर पास करके पिटीशन को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता।

केजरीवाल ने ट्रांसफर करने की मांग की थी

दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की क्रिमिनल पिटीशन को ट्रांसफर करने की मांग की थी. केजरीवाल इस मामले में रेस्पोंडेंट में से एक हैं. सीबीआई की याचिका पर 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

बरी किए गए सभी 23 लोगों को नोटिस

उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत शराब नीति मामले में बरी किए गए सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च तय की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि शराब नीति मामले में आप नेताओं केजरीवाल, सिसोदिया और दूसरे सभी आरोपियों को बरी करते समय गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां, चार्ज स्टेज पर, पहली नज़र में गलत हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा था कि 9 मार्च के ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों में खास गड़बड़ी के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है. संबंधित बेंच ने एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े कई मामलों पर पहले ही फैसला कर लिया है, जिसमें पहली नजर में टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

केजरीवाल ने अर्जी में क्या कहा

अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है. उन्होंने कहा कि उनकी दलील किसी निजी पसंद पर आधारित नहीं है, बल्कि सिर्फ एक निष्पक्ष और जानकार लिटिगेंट के मन में एक वाजिब आशंका को परखने के लिए है. इसलिए गंभीर, सच्ची और वाजिब आशंका के आधार पर ट्रांसफर की मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और न्यूट्रैलिटी वाली सुनवाई नहीं हो सकती है।

राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

27 फरवरी को फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप सह-आरोपी या गवाहों के बयानों पर आधारित थे, लेकिन उन्हें किसी भी आपराधिक साजिश से जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र सबूत नहीं था. इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि ष्ब्ठप्ष् ने लंबे समय तक सरकारी गवाह के बयानों को बार-बार दोबारा रिकॉर्ड किया, जाहिर तौर पर कमियों को भरने, सरकारी वकील की कहानी को बेहतर बनाने, और आरोपियों को फंसाने, या हालात की चेन में गायब कड़ियों को बनावटी ढंग से जोड़ने के लिए.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कही ये बात

9 मार्च को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि आरोप लगाने के स्टेज पर ही, गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की कही गई कुछ बातें पहली नज़र में गलत लगती हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है।

शेष खबर पेज न 12 पर

ईरान ने भारतीय जहाजों को 'हरी झंडी' दी, कहा- 'भारत हमारा दोस्त है, हम सुरक्षित रास्ता निकालेंगे'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पर्शियन गल्फ क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने संकेत दिया है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब इस क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

भारत को लेकर ईरान का सकारात्मक रुख

पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना संबंध हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सुरक्षित रास्ता मिलेगा, तो उन्होंने सकारात्मक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही स्थिति साफ हो सकती है। उनका कहना था कि भारत ईरान का दोस्त है और आने वाले कुछ घंटों में इस बारे में स्पष्ट स्थिति सामने आ सकती है।

क्षेत्रीय हितों पर दोनों देशों की समान सोच

ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत और ईरान के बीच कई क्षेत्रीय हित साझा हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि लंबे समय से दोनों देश कई मुद्दों पर मिलकर काम करते रहे हैं। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच सहयोग और भरोसे का रिश्ता है, जो मौजूदा हालात में भी बना हुआ है।

लंबे समय से बने हुए हैं मजबूत संबंध

राजदूत फतहाली ने कहा कि भारत और ईरान के संबंध दोस्ती और सहयोग पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से अच्छे रिश्ते रहे हैं और कई क्षेत्रों में साझेदारी भी रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा हित और समान सोच होने के कारण आपसी सहयोग हमेशा मजबूत बना रहा है।

मुश्किल समय में भारत के सहयोग का जिक्र

अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने कठिन समय में ईरान का साथ दिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में ईरान की मदद की है। उनके मुताबिक युद्ध के बाद की परिस्थितियों में भी भारत ने सहयोग किया, जो दोनों देशों के भरोसे और रिश्तों को मजबूत बनाता है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की रणनीतिक अहमियत

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। इस संकरे समुद्री रास्ते से वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और व्यापार पर असर डाल सकता है। भारत के लिए भी यह मार्ग बेहद अहम है, क्योंकि देश अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है।

वैश्विक व्यापार पर भी पड़ता है असर

अगर इस समुद्री मार्ग में किसी तरह की रुकावट आती है, तो उसका असर केवल तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश और शिपिंग कंपनियां इस क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

संघर्ष के बीच बढ़ी निगरानी

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ गई है। ऐसे माहौल में ईरान के राजदूत का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि भारत और ईरान के बीच समुद्री आवाजाही को लेकर सहयोग जारी रह सकता है और भारतीय जहाजों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने में सहूलियत मिल सकती है।

संक्षिप्त ख़बरें

भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन और बूथ प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण

गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र स्थित जंग बहादुर लाल बनवारी लाल इंटरमीडिएट कॉलेज में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनकापुर के विधायक रमापति शास्त्री सहित जिले के कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों, उनके क्रियान्वयन, बूथ प्रबंधन, मन की बात टिफिन बैठक, बूथ स्तरीय कार्यक्रम, पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान, इतिहास, विकास कार्यो तथा सोशल मीडिया और नमो ऐप के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। वहीं विधायक रमापति शास्त्री के द्वारा गैस सिलेंडर की किल्लत के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, ये विरोधियों का प्रचार है। उन्होंने प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर कहा कि हमारी सरकार ने सबको साथ लेके चलने का काम किया है। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि वेद प्रकाश दुबे, सांसद गोंडा प्रतिनिधि कमलेश पाण्डेय, जनार्दन प्रसाद तिवारी, बाबूलाल शास्त्री, राकेश तिवारी, योगेंद्र बहादुर श्रीवास्तव, रबी श्रीवास्तव, सतेंद्र श्रीवास्तव, प्रिंस श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा, सौरभ दुबे, विनोद सिंह, पिंकू सिंह, आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ताजमहल से दिल्ली साइकिल यात्रा मथुरा से लौटाई, हिंदू महासभा की हर स्मारक पर तिरंगा फहराने की मांग

आगरा। ताजमहल समेत अन्य स्मारकों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए कानून बनाने की मांग को ताजमहल से शनिवार को दिल्ली तक के लिए शुरू हुई अखिल भारत हिंदू महासभा की यात्रा को पुलिस ने मथुरा में रोक दिया। रिफाइनरी थाना पुलिस ने शांति व्यवस्था को खतरा बताते हुए ज्ञापन ले लिया। कार्यकर्ताओं को आगरा वापस लौटने की हिदायत देते हुए फरह टोल प्लाजा पर छोड़ दिया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर के नेतृत्व में साइकिल यात्रा शनिवार सुबह 11 बजे ताजमहल के पश्चिमी गेट के समीप स्थित आरके फोटो चौराहा से शुरू हुई। उन्हें 18 मार्च को दिल्ली में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपना था। समर्थन मांगने सांसद हेमा मालिनी के निवास पर भी जाना था। मथुरा में जन्मभूमि और ईदगाह पर तिरंगा फहराने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में साइकिल यात्रा को रोककर सभी को थाना ले जाया गया। शाही ईदगाह पर तिरंगा फहराने से शांति व्यवस्था को खतरा बताते हुए यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। महासभा के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लेने के बाद उन्हें फरह टोल प्लाजा पर छोड़ते

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा होगी तय, कमेटी के नामों को केंद्र ने दी मंजूरी, SC में हलफनामा दायर

सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अरावली पहाड़ियों की नयी परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर संज्ञान लेते हुए 20 नवंबर के अपने एक आदेश को स्थगित कर दिया था, जिसमें इन पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावित 10 सदस्यीय हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसे अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा तय करने का कार्य सौंपा गया है. कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कमेटी के लिए सुझाए गए नामों का समर्थन किया है.

इस कमेटी में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे (एफएसआई), जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े वर्तमान तथा सेवानिवृत्त नौकरशाहों के साथ-साथ शिक्षाविद भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

हलफनामे में कहा गया है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निवेदन करता है कि प्रस्तावित कमेटी के गठन के लिए सुझाए गए नामों पर यदि यह न्यायालय विचार करता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. फिलहाल मंत्रालय के पास इस कमेटी में शामिल करने के लिए कोई अतिरिक्त नाम नहीं है।

कंचन देवी करेंगी कमेटी की अध्यक्षता

प्रस्तावित कमेटी की अध्यक्षता इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की वर्तमान डायरेक्टर कंचन देवी करेंगी. अन्य सदस्यों में एफएसआई के पूर्व महानिदेशक सुभाष अशुतोष, जीएसआई के पूर्व निदेशक राजेंद्र कुमार शर्मा, क्लाइमेट एंड एनर्जी पॉलिसी एक्सपर्ट तेजल कानिटकर, वरिष्ठ शिक्षाविद और लाइफ साइंस रिसर्चर जया प्रकाश यादव, वरिष्ठ जियोग्राफर और स्कॉलर तेजबीर सिंह राणा, भारत के पूर्व अतिरिक्त सर्वेयर जनरल, एसवीसिंह, गुजरात के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक सीएन पांडेय, नगालैंड के पूर्व पीसीसीएफ धर्मेंद्र प्रकाश शामिल हैं।

अरावली पहाड़ियों की नयी परिभाषा

सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अरावली पहाड़ियों की नयी परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर संज्ञान लेते हुए 20 नवंबर के अपने एक आदेश को स्थझिगत कर दिया था, जिसमें इन पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था. कोर्ट ने सभी खनन गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी।

सुरियावां में स्वर्णकार संघ का होली मिलन समारोह संपन्न

सुरियावां में स्वर्णकार संघ द्वारा एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के सम्मानित वरिष्ठजनों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देना था। समारोह में उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दीं। वक्ताओं ने इस प्रकार के सामाजिक आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें समाज को एकजुट करने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान, सभी उपस्थित लोगों ने पारंपरिक तरीके से होली का उत्सव मनाया। इस आयोजन के माध्यम से सामाजिक एकता पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री राकेश वर्मा, जिलाध्यक्ष लोकेश सेठ,कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सेठ ,दिनेश सेठ बब्बू, सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। समारोह का समापन होली की शुभकामनाओं और सामाजिक एकता के संकल्प के साथ हुआ,और सदस्यों ने आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया!

कानपुर में क्रूरता की हद, कब्रिस्तान में सो रहे कुत्ते को युवक ने ईंट से कुचलकर मार डाला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। कानपुर में पशु क्रूरता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कब्रिस्तान में सो रहे कुत्ते को एक युवक ने ईट से कुचलकर मार डाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर के कर्नलगंज थानाक्षेत्र स्थित बिसाती कब्रिस्तान में एक युवक की बर्बरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। युवक ने सो रहे एक बेजुबान कुत्ते को ईट से कुचलकर मार डाला। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के बाद पशु प्रेमियों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपित के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की है।

शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ जिसमें एक युवक हाथ में ईट लेकर कब्रिस्तान में टहलते हुए आता है। वहां जमीन पर लेटे कुत्ते को देखकर वह अचानक उस पर ईट से हमला कर देता है। हमले से घायल कुत्ता जान बचाने के लिए उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह गिर पड़ता है। इसके बाद युवक बिना किसी डर के पास पड़ी दूसरी भारी ईट उठाता है और फिर कुत्ते के सिर पर वार कर देता है। इस दौरान वहां मौजूद लोग कर रहे हैं कि अजान हो रही है मत मारो लेकिन वह नहीं मानता है। ताबड़तोड़ प्रहार से कुत्ता मौके पर ही दम तोड़ देता है। घटना का वीडियो प्रचलित होते ही पशु प्रेमियों में रोष फैल गया। इसके बाद पशु प्रेमी दिनेश, अजय मिश्रा, ऋषभ कश्यप, विजय, रोहन समेत एक दर्जन से अधिक लोग कर्नलगंज थाने पहुंचे और आरोपित के खिलाफ तहरीर दी। कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार चौधरी ने बताया कि प्रचलित वीडियो से युवक की पहचान बिसाती कब्रिस्तान निवासी मिराज के रूप में हुई है। रिपोर्ट दर्जकर उसके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

रिटायर महिला कर्मचारी से एरियर भुगतान के लिए ली रिश्वत... डिप्टी C M ब्रजेश पाठक ने लिया एक्शन; गिरी गाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव निलंबित कर दिया गया है. रिटायर महिला कर्मचारी से एरियर भुगतान के बदले 45 हजार रुपये घूस लेने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तत्काल जांच के आदेश दिए. इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया।

रिटायर महिला कर्मचारी ने अपने भाई के साथ मिलकर रिश्वत लेते हुए प्रदीप श्रीवास्तव का वीडिया बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

रिटायर एएनएम से मांगी थी रिश्वत

जानकारी के मुताबिक विक्रमजोत सीएचसी के तहत एएनएम सुनीता कार्यरत थीं. सेवानिवृत्ति के बाद उनके एरियर भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी. आरोप है कि इस भुगतान के बदले वरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव ने उनसे 45 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. पीड़िता सुनीता ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रदीप श्रीवास्तव को रिश्वत देते समय वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

जांच के बाद हुई कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक प्रशासन अलका वर्मा ने आरोपी को निलंबित कर दिया. निलंबन के बाद प्रदीप श्रीवास्तव को चित्रकूट धाम मंडल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय से संबद्ध किया गया है. विभाग ने आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मामले की जांच के लिए चित्रकूट धाम मंडल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कोर्ट के आदेश के बाद भी ली थी रिश्वत

जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला कर्मचारी सुनीता वर्मा का विभाग में काफी समय से एरियर बकाया था. जिसके बाद वह कोर्ट चली गई और कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया था. आरोप है कि इसके बावजूद फाइल आगे बढ़ाने के लिए बाबू प्रदीप श्रीवास्तव ने रिश्वत ली।

जम्मू-कश्मीरः गैस की किल्लत के बीच जमाखोरी का खेल, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, 75 एलपीजी सिलेंडर जब्त

जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. यह कदम आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ईरान अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग से भारत में गैस की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से लोग अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं. इस बीच जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान इलाके से 75 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए. इसके साथ ही अवैध कारोबार में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई विशेष सूचना के आधार पर की गई. एसएसपी डोडा संदीप मेहता (जेकेपीएस) के निर्देशों पर पुलिस स्टेशन भद्रवाह की टीम ने छापेमारी की. दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग भद्रवाह इलाके में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर आम लोगों को बेच रहे हैं और इससे सरकारी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

तीन आरोपी गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पुलिस को उनके कब्जे से बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर मिले. पुलिस के अनुसार, यह सिलेंडर अवैध तरीके से जमा किए गए थे और बाद में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी।

75 एलपीजी सिलेंडर बरामद

पुलिस ने बताया कि अब्दुल हमीद के कब्जे से 8 भरे हुए और 15 खाली एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए. वहीं गुलाम रसूल के पास से 28 भरे हुए और 24 खाली सिलेंडर जब्त किए गए. इस तरह कुल मिलाकर 75 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

मामले की जांच जारी

बरामदगी के बाद भद्रवाह पुलिस स्टेशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.डोडा पुलिस ने दोहराया कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जो आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है

अफवाहों से ऊपर उठकर भरोसा रखें: वैश्विक संकट के बीच सरकार की कोशिशों पर विश्वास जरूरी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की परिस्थितियों का असर अब दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोगों के बीच चिंता का माहौल दिख रहा है। कुछ स्थानों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन खबरों के बीच अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ रही है।

लेकिन ऐसे समय में संयम और भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। देश की सरकार और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। संकट के समय अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करना ही समझदारी का परिचय है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। समुद्री मार्गों से तेल और गैस की सप्लाई में बाधाएं आने के कारण कई देशों को आपूर्ति प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी दुनिया के अन्य देशों की तरह इस वैश्विक परिस्थिति से पूरी तरह अलग नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हालात का प्रभाव यहां भी महसूस होता है।

हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जो लगातार गैस की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा कर रही है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी स्थिति में आम उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई सीमित कर दी गई है ताकि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो। इसके साथ ही सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे कदम भी उठाए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य यही है कि गैस की जमाखोरी रोकी जा सके और वास्तविक उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचे। इन परिस्थितियों में कुछ लोगों के बीच घबराहट की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कराने या जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही स्थिति असली संकट को और बढ़ा देती है। जब लोग अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर जमा करने लगते हैं, तो वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक आपूर्ति पहुंचने में दिक्कत होती है। इसलिए सरकार ने बार-बार अपील की है कि लोग घबराहट में अतिरिक्त सिलेंडर बुक न करें और अफवाहों से दूर रहें।

इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद मोडिबने भी लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर जरूर पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार हर स्थिति में 'इंडिया फर्स्ट' की नीति के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सही व सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें। उनका यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकट के समय घबराहट से ज्यादा नुकसान होता है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी शुरू कर दी हैं। खबर है कि भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में आपूर्ति की कमी न हो। भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल के कई सौदे किए हैं और कई तेल टैंकरों ने अब भारतीय बंदरगाहों की ओर रुख कर लिया है। इससे आने वाले समय में ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। इतिहास गवाह है कि भारत ने इससे पहले भी कई वैश्विक संकटों का मजबूती से सामना किया है। चाहे महामारी का दौर रहा हो, आर्थिक चुनौतियां हों या अंतरराष्ट्रीय तनाव हर बार देश ने संयम और सामूहिक सहयोग के बल पर परिस्थितियों को संभाला है। आज भी यही जरूरत है कि नागरिक सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें और जिम्मेदार व्यवहार करें। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी बड़े देश में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह एक समान नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में अस्थायी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे देश में स्थायी संकट खड़ा हो गया है। वितरण व्यवस्था को संतुलित करने में समय लग सकता है, लेकिन सरकार और कंपनियां लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। संकट के समय समाज की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जरूरत से ज्यादा खरीदारी या जमाखोरी से बचना, अफवाहें न फैलाना और दूसरों को भी सही जानकारी देना हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति संयम बरते तो किसी भी अस्थायी कठिनाई को आसानी से दूर किया जा सकता है। आज देश को घबराहट नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री की अपील भी यही है कि अफवाहों से दूर रहें और देश की सामूहिक शक्ति पर भरोसा रखें।

आखिरकार भारत जैसे बड़े और मजबूत देश के लिए यह चुनौती स्थायी नहीं है। थोड़े समय की कठिनाई के बाद स्थिति सामान्य होने की पूरी संभावना है। ऐसे समय में नागरिकों का विश्वास और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर देश के लोग संयम और समझदारी के साथ काम लें, तो किसी भी संकट को अवसर में बदला जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अफवाहों से दूर रहते हुए धैर्य बनाए रखा जाए और सरकार की कोशिशों पर भरोसा किया जाए। यही विश्वास देश को हर कठिन परिस्थिति से निकालने की ताकत देता है और यही भारत की असली शक्ति भी है।

कांतिलाल मांडोत

भारत का अरबपति युग: समृद्धि की चकाचौंध या असमानता की आहट?

[समृद्धि की ऊँची मीनारें और नीचे फैलती असमानता]

[धन के शिखर पर मुट्ठीभर लोग, संघर्ष में करोड़ों जीवन]

भारत की आर्थिक चमक के पीछे एक तीखा विरोधाभास है। एक ओर प्राइवेट जेट और लग्जरी यॉट्स की दुनिया, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं। यह दर्शाता है कि देश में धन तेजी से कुछ हाथों में सिमट रहा है, जबकि आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मार्च 2026 तक फोर्ब्स सूची में भारत के 229 अरबपति हैं (पिछले वर्ष 205), जिनकी कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट इसे 308 बताती है। 99.7 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं, जबकि गौतम अडानी सहित कई उद्योगपति अरबों की संपत्ति के शिखर पर हैं। पर इस समृद्धि का लाभ निचले तबकों तक नहीं पहुंच रहा और बढ़ती असमानता सामाजिक संतुलन को कमजोर कर रही है। अरबपतियों की बढ़ती संख्या संयोग नहीं है। शेयर बाजार की तेजी, आईपीओ की लहर और फिनटेक, एआई व एडटेक जैसे नए क्षेत्रों ने कई नए अरबपति पैदा किए हैं। फोर्ब्स 2026 के अनुसार इस वर्ष 30 नए अरबपति जुड़े, जिनमें कई 30-35 वर्ष के युवा हैं। रेजरपे और फिजिक्सवाला जैसे स्टार्टअप्स के संस्थापकों ने कुछ ही वर्षों में अरबों की संपत्ति बनाई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों ने भी धन कई गुना बढ़ाया है। लेकिन यह समृद्धि समावेशी नहीं है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% के पास मात्र 6.4%। शीर्ष 10% के पास 65% संपत्ति और 58% आय है, जबकि आधी आबादी को केवल 15% आय मिलती है। साफ है कि विकास का लाभ कुछ ही हाथों में सिमटा है।

बढ़ती आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। एक ओर अरबपति प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, तो दूसरी ओर करोड़ों परिवार महंगाई के बोझ तले दबे हैं। खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, पर मजदूरी लगभग स्थिर है। शिक्षा और स्वास्थ्य की असमान पहुंच गरीबों को और पीछे धकेलती है। सामाजिक गतिशीलता ठहर गई है और गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्टों के अनुसार अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी है, जबकि गरीबी घटाने के प्रयास कमजोर हैं। भारत में करोड़ों लोग न्यूनतम आय पर निर्भर हैं। यह बढ़ती खाई सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और जाति-लैंगिक असमानता को और गहरा कर रही है।

धन-विभाजन की मानसिकता भारतीय समाज में गहराई से जमी रही है। कभी अमीरों को 'महाजन' या 'सेठ' कहकर सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस के दौर में सवाल उठ रहे हैं—जब लाखों लोग भूखे हैं, तो कुछ के पास अपार धन क्यों? अमर्त्य सेन जैसे विचारकों के अनुसार असमानता विकास की बड़ी बाधा है, जो सामाजिक न्याय और एकता को कमजोर करती है। धन का केंद्रीकरण जाति, लिंग और क्षेत्रीय असमानताओं को और गहरा करता है, जिसका सबसे ज्यादा असर दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर पड़ता है। अमीरों की भव्य जीवनशैली गरीबों में असंतोष बढ़ाती है। इसलिए समाज को समझना होगा कि धन केवल निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है—अन्यथा असमानता सामाजिक विखंडन को और तेज करेगी। आर्थिक नीतियों के भीतर छिपे कारण भी असमानता को बढ़ाते हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद बाजार-केंद्रित विकास का लाभ मुख्यतः अमीर वर्ग को मिला, जबकि गरीब हाशिये पर रह गए। क्रोनी कैपिटलिज्म और राजनीतिक संबंधों से लाभ उठाने वाले उद्योग इस खाई को और गहरा करते हैं। कर व्यवस्था भी असंतुलित है—अमीरों पर कम प्रत्यक्ष कर, जबकि गरीब जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों का अधिक बोझ उठाते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2014-2025 के दौरान आय असमानता स्थिर दिखी, लेकिन धन लगातार ऊपर ही केंद्रित होता गया। जीडीपी बढ़ी, पर आम आदमी की क्रय शक्ति और रोजगार उतने नहीं बढ़े। नीतियां भी अक्सर प्रभावशाली वर्ग के पक्ष में झुकती हैं, जिससे लोकतंत्र पर धन का प्रभाव बढ़ने लगता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की असमानता बेहद तीखी है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत में शीर्ष 10% और निचले 50% के बीच आय का अंतर दुनिया में सबसे अधिक है। जहां यूरोप में यह अंतर अपेक्षाकृत संतुलित है, वहीं भारत और थाईलैंड जैसे देशों में शीर्ष 10% के पास लगभग 65% संपत्ति केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष 1% के पास 37% संपत्ति है, जबकि आधी आबादी के हिस्से केवल 2% संपत्ति आती है। स्कैंडिनेवियाई देशों की तरह उच्च कर और मजबूत सामाजिक कल्याण नीतियों से इस असंतुलन को कम किया जा सकता है। अन्यथा समय रहते सुधार न होने पर यह खाई और गहरी होकर सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है। समाधान संभव हैं, बशर्ते राजनीतिक और सामाजिक इच्छाशक्ति हो। प्रगतिशील कर व्यवस्था के तहत अमीरों पर वेल्थ टैक्स और अधिक आयकर लगाकर संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाया जा सकता है। एमएसएमई और कौशल विकास को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और न्यूनतम आय गारंटी जैसे कदम भी सहायक हो सकते हैं। साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रभावी बनाकर उद्योगपतियों की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सफैम के अनुसार वेल्थ टैक्स जैसी नीतियां असमानता कम करने में कारगर हो सकती हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि भारत की बढ़ती अरबपति चमक के पीछे छिपी असमानता को गंभीरता से समझा जाए। सच्चा और समावेशी विकास तभी संभव है, जब धन-विभाजन की सोच बदले और आर्थिक असमानता को कम करने के ठोस प्रयास हों। यदि यह खाई यूँ ही बढ़ती रही, तो समाज गहरे विभाजन की ओर बढ़ेगा। इसलिए ऐसा भारत बनाना होगा जहां संपत्ति कुछ हाथों तक सीमित न रहकर सबके उत्थान का माध्यम बने, क्योंकि गहरी असमानता वाला समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

संस्कार विहीन आधुनिकता समाज के लिए घातक

संस्कार-संस्कृति का जीवन में विशिष्ट महत्व

भारतीय समाज एक बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक, बहुजातीय, बहु धार्मिक समाज है। एक नजर में इसकी प्रगाढ़ता और इसके विराट स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। भारतीय समाज की गहरी और विशाल संरचना को, उसके विभिन्न आयामों को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। हमारा समाज एक विशिष्ट और उत्कृष्ट समाज है, जो अनेक संस्कृतियों, रीति-रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और जीवनशैली में गुथा हुआ है। रोजमर्रा की जीवन शैली में भारतीय समाज की विशिष्ट पहचान दृष्टिगोचर होती है। यह समाज जहां अपनी पुरातन रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ा है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विकास के साथ अग्रसर होने की चाह में आगे बढ़ रहा है। भारतीय समाज रूढ़िवादिता और आधुनिकता के विकास के बीच अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। एक और भारतीय समाज पश्चिम से प्रेरित होकर भौतिकता की चकाचौंध के पीछे भाग रहा है वहीं दूसरी तरफ अपनी पुरातन आध्यात्मिक परंपराओं का भी बखूबी निर्वाहन करने का प्रयास भी कर रहा है। किंतु समाज में यह अंतर्द्वंद बना हुआ है कि वह योग को अधिक महत्व दे अथवा भोग को, इससे इतर भारतीय समाज आश्चर्यजनक रूप से दोनों को अपनाते हुए आगे की ओर अग्रसर है। भारतीय महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई परिभाषाएं लिख नहीं है वही देश में शिशु लिंगानुपात हर जनगणना में घटता जा रहा है। सामाजिक कुरीतियों में कमी तो आई है पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और यौन अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमारे समाज में बेटियां नाम कमा कर माता-पिता का नाम रोशन तो तेजी से कर रही हैं पर भ्रूण हत्या की दरों में अनावश्यक तेजी भी चिंता का कारण बनी हुई है। यही अंतर्विरोध ही समाज को चिंतनीय भी बना रहा है। सबसे ताजा खबरों में हरनाज संधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, और देश का नाम ऊंचा कर गौरव हासिल किया है। भारतीय लड़कियों ने फैशन में एक नया मुकाम बनाया है आज आधुनिक पेंट, जींस पहन कर लड़कियां आगे बढ़ने को आतुर है। दूसरी तरफ खानपान में जहां भारतीय पारंपरिक व्यंजन डोसा, सांभर, इडली, पंजाबी ,मसालेदार भोजन ग्लोबल स्तर पर छा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पारंपरिक भोजन ही कर रहे हैं हमने पिज़्ज़ा, पास्ता, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीस और कॉन्टिनेंटल फूड को भी आमजन का खाद्य पदार्थ बनाया हुआ हैं। भारतीय समाज अंत्येष्टि रूढ़िवादी संस्कारों को पूरी तरह निभाने का प्रयास कर रहा है दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप में युवक युवतियां महानगरों में बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं। रूढ़िवादिता तथा पश्चिम के खुले पन और उन्मुक्त होता का एक फ्यूजन तैयार हो रहा है। हमारा समाज आधुनिक अनश्वर को अपनाता है दूसरी तरफ नवीन वैज्ञानिक पद्धति को भी अपना रहा है और नवयुग की ओर आकर्षित हो रहा है। दूसरी तरफ अपने पारंपरिक दार्शनिक धार्मिक मूल्यों जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म मार्ग, अवतारवाद, पुनर्जन्म, आस्था तथा मोक्ष की अवधारणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर अभी भी आस्थावान है। धर्म तथा अध्यात्म का आकर्षण कम होने के स्थान पर ज्यादा हुआ है। धार्मिक स्थलों के बढ़ते निर्माण धर्म गुरु के सत्संग, प्रवचन, पूजन, भजन ,कीर्तन, अजान ,अरदास, उपवास, रोजा, तीर्थ स्थलों, दरगाह पर भारी भीड़ यह सब सिद्ध करते हैं कि भारतीय समाज आधुनिक होने के साथ-साथ रूढ़िवादिता पर भी विश्वास रखता है। इन्हीं सब कारको के कारण रूढ़िवादिता तथा पाश्चात्य दर्शन का अंतर्विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए हम भारतीय समावेशी विकास की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर खनन, पेडो की बेतरतीब कटाई जारी रख पर्यावरण की धज्जियां उड़ाते हैं। जल, जंगल, जमीन से लेकर हवा तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इससे रूढ़िवादिता और पश्चिमीकरण मैं द्वंद स्पष्ट उजागर होता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज ने अपने संविधान के निर्माण और व्यवस्था के गठन तक में रूढ़िवाद और आधुनिकता दोनों का समन्वय बनाकर दोनों ही वाद को पर्याप्त स्थान दिया है। परंपरागत मूल्यों को जहां मौलिक कर्तव्य राज्य नीति के निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में स्थान दिया है। इसके अलावा मौलिक आजादी के समानता के सिद्धांत को फ्रांस से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और मानवीय मूल अधिकार को अमेरिका से ग्रहण करने में जरा भी संकोच नहीं किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्तर पर भी भारतीय समाज रूढ़िवादिता और आधुनिकता की ओर एक साथ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एलोपैथी पद्धति से इलाज ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है वही आयुर्वेद योग, परंपरागत आयुर्वेद, ध्यान, नेचुरोपैथी आदि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में भी लोगों की रुची बड़ी तेजी से बढ़ी है। रविंद्र नाथ टैगोर जी ने कहा है 'आधुनिकता पोशाक में नहीं विचारों में होनी चाहिए'

भारतीय समाज बाह्य वस्तुओं के साथ-साथ वैचारिक और संस्कृति स्तर पर भी रूढ़िवादिता और आधुनिकता दोनों की ओर एक साथ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ऐतिहासिक तौर पर भी भारतीय कला और संस्कृति का विकास स्वयं में रूढ़िवादिता और आधुनिकता के समन्वयक का उत्कृष्ट उदाहरण अमीर खुसरो भारतीय वीणा और इरानी तंबूरे को मिलाकर सितार बना रहे थे। स्थापत्य की नागर शैली व मूर्ति कला की गंधार शैली अलग-अलग भारतीय व बाह्य कलाओं के समन्वय का उत्कृष्ट परिणाम है। मुस्लिम स्थापत्य पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हिंदी और फारसी के सहयोग से उर्दू का जन्म भारतीय समाज की ही देन है। इसीलिए यह बात स्पष्ट है कि रूढ़िवादिता और पाश्चात्य दर्शन के अनुसरण के लिए भारतीय जनमानस को दोनों दर्शन के सर्वोत्कृष्ट तत्वों को चुनकर उसे अंगीकार करना चाहिए। जिससे भारतीय समाज में विकास की गति भारतीय संस्कृति तथा आधुनिकता के साथ साथ तीव्र गति से हो पाए और मानव कल्याण संभव हो पाए।

संजीव ठाकुर

संपादकीय

हॉर्मुज की घेराबंदी और भारत में गहराता गैस संकट

भारत की ऊर्जा सुरक्षा आज एक ऐसे कठिन मोड़ पर खड़ी है जहाँ सरहद पार की जंग हमारे रसोई घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की दहलीज तक पहुँच गई है। देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में आई अचानक गिरावट ने न केवल होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की कमर तोड़ दी है, बल्कि आम नागरिक के मन में भी भविष्य को लेकर एक अनजाना डर पैदा कर दिया है। यह संकट केवल मांग और आपूर्ति का साधारण गणित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति, युद्ध की विभीषिका और भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता का एक कड़वा परिणाम है। नई दिल्ली के गलियारों से शुरू हुई यह सुगबुगाहट अब पूरे देश में एक बड़े हड़कंप का रूप ले चुकी है, जहाँ उत्तर से दक्षिण तक गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें एक गहरे संकट की गवाही दे रही हैं। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया है, ताकि जमाखोरी जैसी कुप्रथाओं पर लगाम कसी जा सके और उपलब्ध संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके।

इस पूरे संकट की जड़ें मध्य पूर्व के अशांत भूगोल में धंसी हुई हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक, हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। मात्र 167 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार की धड़कन माना जाता है। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत कच्चा तेल और 54 प्रतिशत एलएनजी (LNG) इसी मार्ग के जरिए मंगाती है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने इस मार्ग को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है, जिससे टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इसके साथ ही, पिछले दिनों ईरान द्वारा अमेरिका के सहयोगियों कतर, यूएई और कुवैत के ठिकानों पर किए गए ड्रोन हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है। विशेष रूप से कतर में एलएनजी प्लांट पर हुए हमलों के बाद उत्पादन रोकना पड़ा है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि हम अपनी वार्षिक एलएनजी जरूरतों का 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले कतर से पूरा करते हैं। भारत के भीतर इस अंतरराष्ट्रीय संकट का असर सबसे पहले कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गैस वितरण को चार स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है। प्राथमिकता की पहली श्रेणी में घरेलू रसोई गैस (PNG) और सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी को रखा गया है, ताकि आम जनता का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त न हो। दूसरी श्रेणी में खाद कारखानों को रखा गया है, जिन्हें 70 प्रतिशत आपूर्ति दी जा रही है, बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि इस गैस का उपयोग केवल उर्वरक उत्पादन में ही हुआ है। तीसरी श्रेणी में चाय की फैक्ट्रियों जैसे बड़े उद्योगों को रखा गया है, जो 80 प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। सबसे अंतिम और चौथी श्रेणी में छोटे कारखाने, होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं, जिन्हें उनकी पुरानी खपत के आधार पर अधिकतम 80 प्रतिशत सप्लाई का आश्वासन दिया गया है। हालांकि, धरातल पर स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है और कई छोटे प्रतिष्ठानों को तो पूरी तरह गैस मिलना बंद हो गई है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में स्थिति विकट हो चली है। यहाँ बुकिंग के कई दिनों बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही है और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में गैस एजेंसियों के बाहर एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तेल कंपनियां अपना पूरा ध्यान घरेलू उपभोक्ताओं पर केंद्रित कर रही हैं, जिसके कारण ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने अपने शटर गिराने की नौबत आ गई है। यही हाल महाराष्ट्र का है, जहाँ मुंबई के लगभग 20 प्रतिशत रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। पुणे में तो संकट इतना गहरा गया है कि नगर निगम को अस्थायी रूप से गैस आधारित शवदाह गृहों को भी बंद करना पड़ा है। 'आहार' जैसे रेस्टोरेंट एसोसिएशनों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटों में आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो आधे से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के होटल संचालक शादी के इस व्यस्त सीजन में सिलेंडर न मिलने से हताश हैं, जबकि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थिति यह है कि कई रेस्टोरेंट्स में केवल कॉफी उपलब्ध है क्योंकि मुख्य भोजन बनाने के लिए गैस ही नहीं बची है। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने युद्ध स्तर पर कदम उठाए हैं। इंडियन ऑयल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) के कार्यकारी निदेशकों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो हर घंटे सप्लाई की समीक्षा कर रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करना सरकार का एक शक्तिशाली कदम है, जो उसे अनाज, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की कीमतों और स्टॉक को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। इसके तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय कर दी गई है ताकि कोई भी इस संकट का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न कर सके। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं; अब एक सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग संभव होगी। इसके अलावा, ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सिलेंडर की कालाबाजारी रोकी जा सके। सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

संकट के बीच सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 913 रुपये का हो गया है। वहीं, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपये का इजाफा हुआ है। यह आर्थिक बोझ आम आदमी और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रहा है। हालांकि, इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि सरकार वैकल्पिक मार्गों और स्रोतों की तलाश कर रही है। जी7 देश अपने इमरजेंसी तेल भंडार से सप्लाई जारी करने पर चर्चा कर रहे हैं और भारत को उम्मीद है कि रूस और अल्जीरिया से अतिरिक्त कच्चा तेल आने के बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन यह समाधान तात्कालिक हैं और लंबे समय में भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

यह संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चेतावनी की तरह है। मध्य पूर्व की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर हमारी रसोई तक पहुँचना यह दर्शाता है कि हम एक नाजुक संतुलन पर टिके हुए हैं। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लानी होगी। अक्षय ऊर्जा, बायोगैस और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार अब केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गए हैं। देश को अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और अधिक मजबूत करना होगा ताकि किसी भी वैश्विक बाधा की स्थिति में हमारे पास कम से कम 90 दिनों का बैकअप मौजूद हो। इसके साथ ही, घरेलू स्तर पर नेचुरल गैस के उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।

कुल मिलाकर, वर्तमान गैस संकट मध्य पूर्व की उथल-पुथल का एक काला आईना है जो हमें आत्मनिर्भर बनने की सीख दे रहा है। यद्यपि सरकार के प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से यह संकट आने वाले कुछ हफ्तों में टल सकता है, लेकिन इससे मिलने वाला सबक स्थायी होना चाहिए। रेस्टोरेंट और होटल उद्योग, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे बचाने के लिए त्वरित और ठोस हस्तक्षेप की जरूरत है। साथ ही, आम नागरिक को भी पारदर्शी जानकारी के माध्यम से विश्वास में लेना होगा ताकि समाज में पैनिक न फैले। ऊर्जा विविधीकरण और आत्मनिर्भरता ही वह रास्ता है जो भारत जैसे विशाल और विकासशील देश को भविष्य के वैश्विक झटकों से सुरक्षित रख सकता है। यह समय एकजुट होकर इस अस्थायी संकट का सामना करने और एक स्थायी, सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की नींव रखने का है।

महेन्द्र तिवारी

अनंतता का सूत्र: पाई और हमारी खोजों की अपरंपार यात्रा

पाई दिवस: विज्ञान, गणित और ब्रह्मांडीय रहस्यों का मिलन

अनंतता की रहस्यमयी गहराइयों में एक अंक चमकता है, जो हर वृत्त, हर आकार और हर गणितीय रहस्य में जीवन फूँकता है– (पाई)। यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है; यह कल्पना, खोज और असीम संभावनाओं का जश्न है, जहाँ हर संख्या अपने भीतर ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को संजोए हुए है। श्व वह अद्भुत शक्ति है जो वृत्तों की परिधि और व्यास के बीच की रहस्यमयी संगति को उजागर करती है, सूर्य और चंद्रमा की गोलाई में छुपी सटीकता को सामने लाती है, और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में छुपे गणितीय जादू को उजागर करती है। यह दिन हमें उस जादुई गणितीय लोक में ले जाता है, जहाँ संख्याएँ नृत्य करती हैं, कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, और हर खोज हमें नए रहस्यों और अनोखे दृष्टिकोणों की ओर ले जाती है। एक ऐसा अंक, जो अनंत तक फैला हुआ है और हर गणितीय रहस्य में अपनी छाप छोड़ता है– (पाई)। 3.141592653... केवल संख्याओं का क्रम नहीं, बल्कि एक कविता की तरह निरंतर बुनाई है, जिसमें कोई दोहराव नहीं और कोई अंत नहीं। यह हर वृत्त की आत्मा है—चाहे वह पृथ्वी का आकार हो, सूर्य का गोलापूर्ण प्रकाश, या आपके हाथ में एक साधारण सिक्का। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे समझने की कोशिश की—मिस्र, बेबीलोन, और यूनानी दार्शनिक आर्किमिडीज तक सभी इसके जादू से मोहित थे। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और माधव ने इसे और परिष्कृत किया, और विज्ञान को नए आयाम दिए। कभी हाथ से लाखों अंकों तक गणना हुई, और आज सुपरकंप्यूटर खरबों अंकों तक इसकी गुत्थियाँ सुलझा रहे हैं। श्व की यह अनंतता मानव जिज्ञासा की अनवरत चुनौती है—यह कहती है, 'और आगे बढ़ो, और जानो।' यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति है– (पाई)। यह केवल गणितज्ञों का खेल नहीं, बल्कि यह वह रहस्यमयी ताकत है जो ग्रहों की कक्षाओं को मापती है, अंतरिक्ष यानों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाती है, और तकनीक की दुनिया में हर महत्वपूर्ण संरचना को आकार देती है। नासा और स्पेसएक्स जैसे मिशनों में श्व की गणना प्रत्येक उड़ान का मार्गदर्शन करती है। इंजीनियरिंग में यह पुलों, ऊँची इमारतों और सुरंगों की डिज़ाइन को परिपूर्ण बनाती है। तकनीकी उपकरण—जीपीएस, सैटेलाइट और स्मार्टफोन—श्व के बिना अधूरे हैं। चिकित्सा विज्ञान में भी यह अद्भुत है—एमआरआई की जटिल गणनाओं से लेकर शरीर के बायोमेट्रिक विश्लेषण तक, श्व हर कदम पर हमारे साथ है। यह विज्ञान की नींव को मज़बूत करता है और मानव सभ्यता को प्रगति के नए आयामों की ओर ले जाता है।

एक संख्या के जश्न के लिए पूरे विश्व में एक दिन समर्पित है - 14 मार्च, जब पाई (पाई) का उत्सव मनाया जाता है। यह तारीख 3.14 के प्रारंभिक अंकों से मेल खाती है, और इसी छोटे क्रम ने 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरी शॉ को इस दिन को उत्सव के रूप में चिह्नित करने के लिए प्रेरित किया। तब से यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि गणित और विज्ञान के प्रति उत्साह और जिज्ञासा का प्रतीक बन गया है। दुनिया भर में इसे मनाने के अनगिनत तरीके हैं—अमेरिका में 'पाई खाने' का मज़ा, जहाँ शब्द 'Pie' और पाई का स्वाद एक साथ मिलता है। गणितीय पहेलियाँ, पाई के अंकों को याद करने की प्रतियोगिताएँ (70,000 से अधिक अंकों तक का रिकॉर्ड), और विज्ञान के प्रयोग इस दिन को जीवंत और रोमांचक बनाते हैं। यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान और जिज्ञासा के अनंत पथ की दिशा दिखाता है। हर चीज़ में छिपा है एक अदृश्य जादू– (पाई)। यह सिर्फ गणित की दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है—सुबह की घड़ी के गोल चेहरे में, कार के पहियों की घूमती परिधि में, संगीत की तरंगों में, और दोस्तों को भेजी गई लोकेशन में भी। प्रकृति में इसकी उपस्थिति और भी आश्चर्यजनक है—फूलों की पंखुड़ियों की घुमावदार आकृतियों में, नदियों की लहराती धाराओं में, और आकाशगंगाओं की विशाल संरचनाओं में इसकी गूँज सुनाई देती है। पाई केवल एक संख्या नहीं, बल्कि वह रहस्यमयी सूत्र है जो सृष्टि को सामंजस्यपूर्ण बनाता है, हर प्रणाली में संतुलन और सुंदरता भरता है, और हमें यह याद दिलाता है कि गणित सिर्फ अंक नहीं, बल्कि जीवन का जादू है। जब हम अनंतता और रहस्यों की असीम गहराइयों में कदम रखते हैं, तब (पाई) हमें यह याद दिलाता है कि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की छिपी हुई भाषा है, जो हर प्रणाली, हर संरचना और हर जीवन के रूप में अपनी छाप छोड़ती है। 14 मार्च को इस अद्भुत गणितीय महोत्सव में खुद को पूरी तरह डुबो दें। की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करें, विज्ञान और खोज की असीम संभावनाओं को अपनाएँ, और उस जिज्ञासा और उत्साह का उत्सव मनाएँ, जो हमें हर दिन नई ऊँचाइयों, नए दृष्टिकोणों और नए रहस्यों की ओर ले जाता है। केवल एक संख्या नहीं—यह अनंतता का दर्पण है, जिसमें हमारी खोजों, हमारी कल्पना और हमारी अनवरत उत्सुकता की चमक झलकती है, और हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।

कृति आरके जैन

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254,** E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

बबौना गांव के पास पिकअप ने साईकिल को मारी टक्कर, दो घायल

मितौली खीरी। लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर बबौना गांव के पास पिकअप ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी जिसमें एक लड़की और एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी जनपद मितौली क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर स्थित बबौना गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने साईकिल को टक्कर मार दी जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक लड़का व एक लड़की हैं। घायल लड़की ने अपना नाम काजल मिश्रा तथा घायल लड़के का नाम दिवाकर मिश्र बताया । घायल दोनों भाई बहन हैं तथा पिता का नाम अमरनाथ बताया। दोनों ओलियापुर बल्लीपुर के निवासी हैं तथा कस्ता में परीक्षा देने जा रहे थे। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलवा कर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली भेज दिया गया है।

लालानगर टोल प्लाजा के पास अव्यवस्था से बढ़ रहा हादसों का खतरा

गोपीगंज । स्थानीय राजमार्ग पर स्थित लालानगर टोल प्लाजा के पास यातायात व्यवस्था की लापरवाही के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यहां ट्रक और चार पहिया वाहन चालक अक्सर बीच सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बताया जाता है कि मौके पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों और टोल कर्मचारियों की अनदेखी के कारण यह स्थिति लगातार बनी रहती है। कई बार वाहनों के बीच रास्ता रोकने को लेकर वाहन चालकों में कहासुनी और विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे मारपीट तक की नौबत आ जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि टोल प्लाजा के आसपास वाहनों को सड़क किनारे व्यवस्थित खड़ा कराया जाए तो दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो सकती है। नागरिकों ने नवागत पुलिस अधीक्षक का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए पतंजलि के जिला प्रभारी रामजी पाल ने मांग की है कि टोल प्लाजा के पास बीच सड़क पर वाहनों को खड़ा करने पर सख्ती से रोक लगाई जाए और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

समाजवादी पार्टी ने कांशीराम की 92वीं जयंती पीडीए दिवस के रूप में मनाई

भदोही। समाजवादी पार्टी भदोही द्वारा जिला कार्यालय (लोहिया ट्रस्ट) कंसापुर, ज्ञानपुर में कांशीराम की 92वीं जयंती पीडीए दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि कांशीराम सामाजिक परिवर्तन के महानायक थे, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित करने का कार्य किया।गोष्ठी को विधायक जाहिद बेग, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, पूर्व विधायक मधुबाला पासी, अंजनी सरोज, राजेन्द्र दुबे और सरिता बिंद ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिलामहासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने किया। इस दौरान संतोष यादव, केश नारायण यादव, सलाउद्दीन अंसारी, डॉ. पवन विश्वकर्मा, महेश पाल, दिलीप पासी, गुलाब पाल, मनोज यादव, कमला महतो, पंचलाल सरोज, राजेश राय, लालजीत दुबे, महेन्द्र गोड, सूबेदार विश्वकर्मा, प्रमोद यादव, श्यामधर यादव, अच्छेलाल सरोज, रवि यादव, शिवदीप यादव, अंकिता राजपूत, सौरभ यादव, गामा प्रसाद यादव, संदीप यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र पप्पू भी मौजूद रहे।

महा खुलासा; फर्जी बरसात के विवाद में फिर फंसे लेखपाल भूपेंद्र वर्मा

● रक्षक ही बने भक्षक लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक के इस खेल में शामिल होने के आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखीमपुर/गोला खीरी- जनपद में राजस्व विभाग के भ्रस्टाचार का एक ऐसा सनसनी खेज मामला सामने आया है।जिसने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।आम आदमी जिस पटवारी और कानूनगो, तहसील दार पर भरोसा करता है और अपनी पूरी जिन्दगी की कमाई लगाता है ।फिर यदि वही अधिकारी कर्मचारी अगर भू माफिया के साथ मिल जाये तो न्याय की उम्मीद किससे की जाय?

क्या है पूरा मामला '..........

तहसील गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत ग्राम सभा हरदुआ निवासी किसान हरीराम पुत्र रजई को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जो जमीन उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात है और वह उसके असली मालिक है उसी जमीन को भू माफियाओं का गिरोह लेखपाल भूपेंद्र और कानूनगो से मिलीभगत करके सुनियोजित तरीके से तैयार किए गए कूटरचित दस्तावेज में उनको मृतक दिखा जाएगा और योजना बद्ध ढंग से स्व निर्मित मृत्यु प्रमाणपत्र और कुटुम्ब रजिस्टर की फर्जी नकल तैयार कर जिसमें पिंकी देवी पत्नी बिंदरपाल मौर्य को उसकी पुत्री दिखाकर फर्जी वरासत भरवा ली जाएगी।और लेखपाल कानूनगो विपक्षी लोगों से भारी रिश्वत लेकर फर्जी वरासत कराने में मदद कर देंगे। तहसील गोला में एक ऐसा ही सनसनी खेज मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर तैनात रहे लेखपाल भूपेंद्र द्वारा गांधी छाप काग़ज़ के टुकड़ों की चकाचौंध में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करवाने के नाम पर लाखों की ठगी कर फर्जी वरासत मैं लगाई गई फर्जी जाली रिपोर्ट के मामले सोशल मीडिया से लेकर अखबारी सुर्खियां तक बने हैं। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी लेखपाल भूपेंद्र वर्मा फर्जी वरासतों के विवादों में घिर चुके हैं। भूमि स्वामी हरीराम पुत्र रजई का आरोप है के लेखपाल भूपेंद्र वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में उनको मृतक दिखाते हुए पिंकी पुत्री बिंदरपाल को उनके फर्जी पुत्री दिखाकर लाखों रुपए की ठगी की है जबकि भू स्वामी हरिराम आज भी जीवित हैं। और वह अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी बिरादरी से आते हैं जबकि उनकी फर्जी पुत्री बनी पिंकी देवी पत्नी विंटर पाल मौर्य बिरादरी से आती हैं तो फिर वह हरिराम की पुत्री कैसे हो सकती हैं? यक्ष प्रश्न बना हुआ है उपरोक्त फर्जीवाड़े कर लेखपाल भूपेंद्र वर्मा

द्वारा लाखों की कमाई की गई है सूत्र बताते हैं की हरिराम की फर्जी बेटी बनी पिंकी देवी पत्नी बिंदरपाल गैर बिरादरी की बताई जाती है उक्त मामले में आज तक कार्यवाही ना होना सवाल खड़ा करता है और इसे सक्षम हुक्मरानों की घोर लापरवाही कहा जाए या फिर लेखपाल द्वारा की गई कमाई में भागीदारी समझा जाए।

बड़ा सवाल..........

यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के साथ घटित जलसा जी की घटना का नहीं है बल्कि यह सिस्टम में दीमक की तरह लगे भ्रष्टाचार का सबूत है जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाए तो आम जनता अपनी जमीन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें फर्जी विरासतों के विवादों में फंसे लेखपाल भूपेंद्र वर्मा पर आज तक कोई कार्रवाई न होना प्रशासनिक सस्ती को उजागर करता है अब देखना यह है कि क्षेत्र में चर्चित दबंग किस्म लेखपाल भूपेंद्र वर्मा पर कब तक शिकंजा कस पता है जिला प्रशासन?

सीएमओ ने किया निरीक्षण, गंदगी मिलने पर कार्रवाई

भदोही। जनपद में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला के तहत डेरवा में मुख्य चिकित्साधिकारी संतोष कुमार चक ने स्वास्थ्य शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में बड़े-बड़े जंगली घास उगे पाए गए तथा बाथरूम भी गंदा मिला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। लापरवाही पाए जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने फार्मासिस्ट प्रवीण गुप्ता तथा सफाईकर्मी छोटे लाल का मार्च 2026 माह का सात दिन का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके बाद अपराह्न करीब 4:10 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल नगर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित पाए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ-सफाई, व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।

मामला सिविल कोर्ट में लंबित होने के बावजूद मकान पर कब्जा कराने महानिदेशक पहुंची चौकी कुकुरा पुलिस

● पीड़ित ने लगाई अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखीमपुर खीरी- मामला मैलानी थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी कुकरा का है जहां के काफी ईमानदार और तेज तर्रार चौकी प्रभारी के अजब गजब करना में आए दिन अकबरी सुर्खियां बनते जा रहे हैं सब के सामने न्यायालय की शायद कोई मायने ना रखते हो इसीलिए तो खंजनपुर में मकान का ताला तुड़वाकर विपक्षी गानों को मकान दिलाने पहुंचे थे कुकुर पुलिस चौकी के जांबाज सिपाही विपक्षी गणों से मिल रहे प्रसाद के चलते साहब न्यायालय में पार्टी बनने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं! बताते चलें ग्राम खंजनपुर निवासी राम रतन पुत्र रोशन का एक वाद सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां पेंडिंग है जिसमें अग्रिम सनी तिथि 6 अप्रैल 2026 नियत है उक्तवाद में मकान और जमीन दोनों का वाद चल रहा है इसके बावजूद विपक्षी लोग धन बल के दम पर मैलानी यस एच ओ.और चौकी प्रभारी कुकरा से साठ गांठ कर गरीब आदमी पर पुलिसिया आतंक दिखाकर मकान छोड़ देने की धमकी दी जा रही है और मकान का ताला खोलने का नाजायज दबाव बनाया जा रहा है जब मामला सिविल न्यायालय में लंबित है तो पुलिस को उसमें दखल करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है पुलिसिया उत्पीड़न से आहत वादी मुकदमा राम रतन पुत्र रोशन ने अपर पुलिस अधीक्षक को अपनी व्यथा सुनाई है और न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जबरन कब्जा कराए जाने की बात न्यायालय के समक्ष रखने की बात कही गई है।

आखिर किसके संरक्षण में फल फूल रहा नशा का काला कारोबार

● क्षेत्र में मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने 5 में विफल मैलानी पुलिस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कुकुरा खीरी- थाना मैलानी की पुलिस चौकी कुकुरा क्षेत्र में खुले आम कच्ची शराब का काला कारोबार बेखौफ होते देखा जा रहा है। यहां खुलेआम कच्ची शराब और अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की भारी मात्रा में सप्लाई होती दिखाई पड रहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि कुकुरा चौकी क्षेत्र नशा कारोबार का हब बनकर रह गया है लोगों ने बताया ऐसा नहीं है कि इस काले कारोबार की जानकारी कुकुर पुलिस चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी निरीक्षक मैलानी को नहीं है थाना मैलानी प्रभारी को तो कई बार मामले से अवगत कराया जा चुका है लेकिन साहब ने डायरी में नोट कर कार्रवाई का का कोरा आश्वासन देकर चलता कर दिया और फिर शायद वह डायरी का पन्ना ही गायब हो गया और कार्रवाई महज एक जुमला बनकर रह गई जिम्मेदारों के इस गैर जिम्मेदाराना कार्य शैली से जहां क्षेत्र में नशे का काला कारोबार गति पकड़ता जा रहा है और लोगों को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है यदि समय रहते इस काले कारोबार पर लगाम न लगाई गई तो युवाओं की बड़ी तादाद आसानी से उपलब्ध हो रहे इस नशे के आगोश में समा जाएगी लोगों का कहना है कि बाइकों से नशे की खेप लेकर गांव-गांव और झाला झाला बेचे जा रहे हैं नशीले पदार्थों से कई घर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं और यही नशे के आदि लोग नशे की तलाश में छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे डाल रहे हैं अहम सवाल तो यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इस काले कारोबार पर नकेल कसने में चौकी प्रभारी कुकरा द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है कई कुकरा वासियों ने नाम न उजागर करने के शर्त पर बताया कि यह सारा खेल सेटिंग गेटिंग के चलते ही हो रहा है ऐसे में कारोबार पर रोक लगा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है अब देखना यह है कि इस अवैध व्यवसाय पर रोक लगाई जाती है या फिर यूं ही खेल जारी रहेगा और सरकार के दावों और वादों की धज्जियां उड़ाई जाती रहेगी।

16 मार्च के शैक्षिक भ्रमण के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

फिरोजाबादः- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब, फिरोजाबाद के तत्वाधान में जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद शत्रोहन वैश्य की सहमति एवं निर्देशन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद धीरेन्द्र कुमार के संयोजन में 16 मार्च 2026 को प्रातः 9 बजे आर बी एस इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज, बिचपुरी आगरा का भ्रमण एवं वैज्ञानिक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसका प्रारम्भ विद्यार्थियों की दो बसों को मुख्य अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंजीनियर सुमित प्रताप सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन भी किया जाएगा। डीआईओएस धीरेन्द्र कुमार ने जनपद के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि अपने विद्यालय के कक्षा 9 एवं 11 तक के चयनित मेधावी छात्र एवं छात्राओं को भ्रमण कार्यक्रम के समय से भेजना सुनिश्चित करें। जिला समन्वयक अश्वनी कुमार जैन ने बताया कि इस वैज्ञानिक शैक्षिक भ्रमण एवं वैज्ञानिक व्याख्यान कार्यक्रम में जनपद के 100 विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ प्रतिभाग करेंगे। जिसमें विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण के साथ शोध प्रयोगशालाओं की विस्तृत जानकारी के साथ उन पर व्याख्यान का श्रवण भी करेंगे। जिनमें व्याख्यानकर्ता विज्ञान संचारक डॉ निखिल जैन एवं नेहा अग्रवाल रहेंगे। सभी प्रतिभागियों को जिला विज्ञान क्लब, फिरोजाबाद की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।

सीसीएम बैठक में कल टूण्डला आयेंगे मजदूर मसीहा शिवगोपाल मिश्रा

टूण्डला - ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की सीसीएम बैठक दिनांक 16से 17मार्च को टूण्डला कम्युनिटी हॉल में संपन्न होगी जिसने दिनांक 16/03/2026 को सुबह 10 बजे काली मंदिर के पास यूनियन कार्यालय से रैली निकाली जाएगी जो वहां से चलकर कमेटी हाल न्यू रेलवे कॉलोनी के लिए रवाना होगी उसके तदउपरांत कमेटी हाल में 11 बजे से मीटिंग शुरु की जाएगी। जिसमें मुख्य अतिथि शिवगोपाल मिश्रा और आर डी यादव रहेंगे जिसकी अध्यक्षता आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा करेंगे जिसमें प्रयागराज .झांसी. आगरा. मंडल के पदाधिकारीगण सीसी मेंबर एजीएम मेंबर एवं अनेकों कर्मचारियों तथा टूण्डला के समस्त केंद्रीय व मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

अलग-अलग दो किशोरियों से छेड़छाड़ रिपोर्ट दर्ज एक दलित

बरेली/क्यो लड़ियां- थाना क्षेत्र मे दो किशोरियों के साथ की गई छेड़छाड़ में पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट दर्ज की है यह घटना थाना क्षेत्र के गांव बबूरी व चंदपुर ख्याली राम मैं यह घटनाएं घटित हुई है पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर उनकी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है इसमें गांव बबुरी में घर में सो रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई तो चंद्रपुर ख्यालीराम में छात्र के साथ छेड़छाड़ की गई दोनों घटनाओं को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तहरीर अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

जिलाधिकारी ने किया उपनिरीक्षक परीक्षा का निरीक्षण 121ने छोडी परीक्षा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बरेली/रिठौरा। नगर के दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए इंस्पेक्टर छवि सिंह, मजिस्ट्रेट श्याम नारायण अग्निहोत्री,स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट सुखपाल, केंद्र व्यवस्थापक आशीष कुमार सिंह, के नेतृत्व में दो दिवसीय उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को प्रथम पाली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने केंद्र का औचक निरीक्षण कर परीक्षा कक्षों, में सीसीटीवी कैमरों में परीक्षार्थियों की तलाशी आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्र पर कुल पंजीकृत 480 परीक्षार्थियों में प्रथम पाली में 359 तथा दूसरी पाली में 362 ने परीक्षा दी जबकि

121 ने परीक्षा छोड़ दी।इस दौरान एस आई सतपाल, परीक्षा प्रभारी डॉ सर्वेश कुमार, रघुवीर सरन, कुसुम गंगवार, ब्रजेश शर्मा, प्रदीप कुमार गुप्ता, रामसिंह, डॉ राजेश कुमार गंगवार, मुरारीलाल, लोकेश कुमार, सिद्धि सिंह, गिरजेश कुमारी, बंदना, अमरेश कुमार, वरूण वर्मा सहित तमाम स्टाफ मौजूद रहा।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी किसानों की उम्मीदें: मितौली लघु सिंचाई विभाग में बड़ा घोटाला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मितौली (खीरी): उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ एक ओर किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का दावा कर रही है, वहीं लखीमपुर खीरी जिले के विकासखंड मितौली में लघु सिंचाई विभाग इन दावों को ठेंगा दिखा रहा है। विभाग पर किसानों से अवैध वसूली और घटिया उपकरणों के वितरण के गंभीर आरोप लगे हैं।

सब्सिडी के नाम पर 'अवैध वसूली' का खेल

सूत्रों के अनुसार, शासन द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में जमकर सेंधमारी की जा रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें मिलने वाली निर्धारित सब्सिडी के बावजूद, विभाग के जिम्मेदारों द्वारा उनसे अतिरिक्त अवैध धनराशि वसूली गई है। लघु सिंचाई विभाग वर्तमान में दलालों का अड्डा बन चुका है, जहाँ बिना 'कमीशन' के किसानों की सुनवाई नहीं हो रही।

घटिया इंजनों की सप्लाई, पोल खुलने का डर

विकासखंड में वितरित किए गए 5 ॥क्कके इंजनों की गुणवत्ता पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि यदि इन इंजनों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, तो विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुलनी तय है। घटिया गुणवत्ता के कारण किसानों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है।

50 किमी दूर बुलाकर किसानों का शोषण

संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई जब लघु सिंचाई विभाग के जेई (JE) द्वारा मितौली के किसानों को उनके क्षेत्र के बजाय 50 किलोमीटर दूर ले जाकर इंजन वितरित किए गए। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उन्हें भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का भी

सामना करना पड़ा।

सरकार की छवि को लग रहा बट्टा

स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जेबें भरने के चक्कर में सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किसानों के खून-पसीने की कमाई का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है।अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और शासन के उच्चाधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर क्या कार्रवाई करते हैं? क्या मितौली के पीड़ित किसानों को न्याय मिल पाएगा?

40 दिनों से लापता रितिक का अब तक नहीं लगा सुराग, परिजनों में बढ़ी चिंता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखीमपुर खीरी। मैलानी थाना क्षेत्र के मक्कागंज गांव निवासी 19 वर्षीय रितिक के लापता होने के मामले को लगभग एक 40 दिन बीतने को है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। समय बीतने के साथ-साथ परिजनों की चिंता दृऔर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।परिजनों का कहना है कि रितिक के अचानक लापता होने के बाद से ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा सकी है। परिवार के लोग दिन-रात उसकी तलाश में भटक रहे हैं और हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जा रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि आखिर रितिक धरती में समा गया या आसमान में उड़ गया,

इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। एक माह 10 दिन बीत जाने के बावजूद मामले का खुलासा न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।352परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द रितिक का पता लगाया जाए, ताकि परिवार को राहत मिल सके और सच्चाई सामने आ सके।

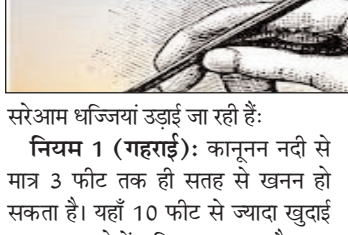

आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव

लखीमपुरः थाना क्षेत्र के पनगी गांव निवासी अंकित (24) पुत्र महेश ने अज्ञात कारणों के चलते बहराइच-बस्ती हाईवे के पास एक आम के पेड़ से गमछे के सहारे फांसी लगा ली। सुबह राहगीरों ने पेड़ से युवक का शव लटका देखा तो इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि अंकित बीती रात से घर से लापता था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। सुबह हाईवे किनारे आम के पेड़ से शव लटका मिलने की खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मामले में पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

मोहम्मदी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिरसा घाट पर 'पीला आतंक

● बालू और मिट्टी के खुले खेल में गोमती का कत्ल, 10 फीट गहरे जख्मों से कराह रही नदी!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहम्मदी खीरी- उत्तर प्रदेश की सियासत में 'बाबा का बुलडोजर' भले ही अपराधियों के घर गिरा रहा हो, लेकिन लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी में यही बुलडोजर और जेसीबी मशीनें गोमती नदी का वजूद मिटाने में लगी हैं। सिरसा घाट पर इन दिनों 'बालू और मिट्टी' का ऐसा खुला खेल चल रहा है, जिसे देखकर कानून और नैतिकता दोनों शर्मसार हैं। यहाँ नियम कागजों पर दम तोड़ रहे हैं और माफिया का 'पीला पंजा' नदी की कोख उजाड़कर करोड़ों के वारे-न्यारे कर रहा है।

1. सिरसा घाटः माफिया का 'ओपन टेंडर' और अवैध साम्राज्य

सिरसा घाट अब कोई शांत नदी का किनारा नहीं, बल्कि माफियाओं की 'अवैध मंडी' बन चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यहाँ बिना किसी खौफ के दिन-दहाड़े और रात के सन्नाटे में सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रालियां बालू और मिट्टी लादकर निकल रही हैं।10 फीट का खूनी खेलः नदी के सीने पर 10 फीट से अधिक गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। माफियाओं की भूख इतनी बढ़ गई है कि वे अब नदी के तल (River Bed) को पूरी तरह खोखला कर चुके हैं। ये गड्ढे नहीं, बल्कि आने वाले मानसून में ग्रामीणों के लिए 'जल-समाधि' की तैयारी है। मिट्टी और बालू के इस अवैध उत्खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह बिगड़ चुका है।

2. खनन के नियमों का 'शवदाह': रक्षक बने भक्षक!

भारत सरकार और एनजीटी (NGT) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की सिरसा घाट पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं:

नियम 1 (गहराई): कानूनन नदी से मात्र 3 फीट तक ही सतह से खनन हो सकता है। यहाँ 10 फीट से ज्यादा खुदाई कर कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है।

नियम 2 (मशीनों का प्रयोग): संवेदनशील नदी क्षेत्रों में भारी मशीनों (Poclain/JCB) का प्रयोग वर्जित है, लेकिन यहाँ दर्जनों मशीनें नदी का सीना चीर रही हैं।

नियम 3 (मिट्टी-बालू का अंतर): मिट्टी खनन के नाम पर बालू (सफेद सोना) निकाला जा रहा है, जिससे सरकार को मिलने वाले राजस्व की भारी चोरी हो रही है।

नियम 4 (ई-पर्चियां): परिवहन के लिए अनिवार्य डिजिटल पास (द्न-स्र्र्रू1) का यहाँ कोई नामोनिशान नहीं है। 'पर्ची' की जगह माफिया का 'रसूख' और 'कमीशन' चलता है।

3. 'संदिग्ध' अफसरः

दलाली की आँच में जलता सुशासनइस पूरे प्रकरण में तहसील मोहम्मदी के प्रशासन और जिला खनन अधिकारी की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की 'मूक सहमति' के बिना इतना बड़ा खेल संभव ही नहीं है। क्या तहसील के आला अफसरों को सिरसा घाट से उड़ती धूल दिखाई नहीं देती? क्या खनन विभाग के कानों तक जेसीबी की गड़गड़ाहट नहीं पहुँचती? सच्चाई यह है कि 'सुविधा शुल्क' के नाम पर भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है, जो माफिया को छापेमारी से पहले ही 'अलर्ट' कर देता है। यह भ्रष्ट तंत्र योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के गले में फांस बन गया है।

4. पर्यावरणिक नरसंहारः डूबता

भविष्य, गिरता जलस्तरमिट्टी और बालू के इस खुले खेल का परिणाम भयावह होने वाला हैः पाताल में जाता पानीः 10 फीट की गहराई तक खुदाई से आसपास के गांवों का 'वाटर टेबल' तेज़ी से गिर रहा है। किसानों के नलकूप जवाब दे रहे हैं।

मिट्टी का कटावः नदी के किनारों को खोखला करने से बरसात में गाँवों के बहने का खतरा बढ़ गया है ।प्रदूषण और तबाहीः भारी वाहनों के आवागमन से न केवल सड़कें टूट रही हैं, बल्कि क्षेत्र की शांति और पर्यावरण भी तबाह हो रहा है।

5. माफिया में हड़कंपः अब 'बुलडोजर' की बारी!

जैसे ही इस महा-घोटाले की खबर नेशनल लेवल पर उठी है, सिरसा घाट के माफियाओं और उनके मददगार अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। मशीनों को रात के अंधेरे में छिपाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लखीमपुर प्रशासन केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति करेगा, या उन 'सफेदपोश मगरमच्छों' को भी पकड़ेगा जो इस अवैध धंधे के असली आका हैं? सिरसा घाट की ये तस्वीरें लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन को मोहम्मदी के खनन माफिया चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि '10 फीट के इन गड्ढों' में कानून दफन होता है या माफिया का साम्राज्य!

संक्षिप्त खबरें

चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, बड़ा हादसा टला

प्रयागराज। औद्योगिक क्षेत्र इलाके में रविवार को चालक की लापरवाही के कारण एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित खाली प्लाट में पलट गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रैक्टर-ट्रॉली को काफी नुकसान पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से गुजर रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। बताया जा रहा है कि चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क से उतरकर पास के खाली प्लाट में पलट गई। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को बाहर निकाला। सौभाग्य से चालक को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। बाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली को क्रेन की मदद से सीधा कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाए जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराने की मांग की है।

टोंस नदी के पुल के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी

प्रयागराज। मेजा थाना क्षेत्र के कोहड़ार इलाके में टोंस नदी के पुल के नीचे रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 32 वर्षीय रजनीश सोनी के रूप में हुई है, जो सोहागी थाना क्षेत्र के कलवारी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार रजनीश सोनी करीब 12 दिन पहले इलाज कराने के लिए मेजा क्षेत्र में आए थे और यहीं ठहरे हुए थे। बताया जाता है कि शनिवार रात वह घर से किसी काम के सिलसिले में निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने रात में ही उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। रविवार सुबह खोजबीन के दौरान टोंस नदी के पुल के नीचे उनका शव पड़ा मिला। यह देख परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण, लापरवाह कर्मियों को दी कड़ी चेतावनी

ब्यूरो प्रयागराज। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरौता विकास खंड मऊआइमा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिगहिंया विकास खंड सोरांव का औचक निरीक्षण किया। तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिगहिंया विकास खंड सोरांव दोपहर 1:00 बजे औचक निरीक्षण में पहुंचे ।प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शमी अहमद अनुपस्थित मिले इनका एक दिन का वेतन बाधित करने का आदेश दिया गया। महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुषमा शुक्ला, श्री हरेंद्र लैब टेक्नीशियन, रिंकू देवी एएनएम श्री धर्मेंद्र कुमार वार्ड ब्वाय उपस्थित थे। श्री राकेश फार्मासिस्ट 11:15 बजे के बाद चले गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पहुंचने तक कुल 15 मरीज देखे गए थे, जिनमें चार की लैब में जांच की गई थी। स्टाक रजिस्टर मांगने पर देखने को नहीं मिला क्योंकि फार्मासिस्ट जा चुके थे। डिलीवरी रजिस्टर पर मंत्रा आईडी नहीं चढ़ाई जा रही थी। पिछली डिलीवरी 7 मार्च 2026 को अंकित की गई थी ।12 मार्च 2026 तक तीन डिलीवरी और हुई थी जिनका अंकन डिलीवरी रजिस्टर पर नहीं किया गया था। इसलिए एएनएम रिंकू देवी को कठोर चेतावनी दी गई ।मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निरीक्षण के समय उनके साथ उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी अरविंद गुप्ता भी थे।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए देश के सात मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना लगाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने निर्देशों का पालन न करने पर देश भर के सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामिल है.खबर के मुताबिक, यह जुर्माना एमबीबीएस इंटर्न और पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट को स्टाइपेंड देने और उनके बारे में जानकारी देने के कमीशन के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। इन सात मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना लगाया गया है- कर्नाटक के देवनहल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर,झारखंड के दिघी में दुमका मेडिकल कॉलेज राजस्थान के बाड़मेर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज,आंध्र प्रदेश के ओंगोल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (पहले राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश के भोपाल में ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तथा हरियाणा के रोहतक में पंडित बीडी शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. एनएमसी सचिव डॉ. राघव लंगर ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मिस भावना तिवारी एवं अन्य (एसएलपी (सी) संख्या 9298/2018) और अभिषेक यादव एवं अन्य बनाम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अन्य (डब्ल्यूपीसी संख्या 730/2022) के मामलों में एनएमसी नियमों और अदालत के आदेशों के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के कारण सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पिछले साल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे लागू नियमों के तहत अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर एमबीबीएस इंटर्न और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंट को दिए जाने वाले स्टाइपेंड की जानकारी दें, ताकि स्टाइपेंड पेमेंट में पारदर्शी और एक समान पक्का हो सके. एनएमसी ने कहा कि, निर्देशों और पालन के लिए दिए गए सही समय के बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ मेडिकल संस्थान आयोग के बताए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं।

प्राप्त डेटा की ठीक से जांच करने के बाद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि सात मेडिकल कॉलेजों ने बार-बार याद दिलाने के बावजूद, मेडिकल इंटर्न को स्टाइपेंड पेमेंट के बारे में जरूरी जानकारी नहीं दी थी.एनएमसी ने कहा कि, ऐसी नाकामी आयोग के दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है और यह नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 और उसके तहत बनाए गए संबंधित नियम के तहत तय नियामक जिम्मेदारियों का पालन न करने के बराबर है।

टापर के नाम की सड़क का नही हुआ टापर के घर तक नवीनीकरण

कोरांव प्रयागराज। कोराव तहसील क्षेत्र के टीकर मर्यादपुर की कुमारी मनोज सिंह टापर इंटरमीडिएट 2017 यूपी बोर्ड (स्टेट रैंक 8) सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोराव प्रयागराज के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2020 में घर तक टापर सड़क योजना के अंतर्गत काली सड़क 2 किलो मीटर का निमार्ण कार्य हुआ जिसका निर्माण प्रार्थी कुमारी मनोज सिंह के IGRS PWD 400175253775 कप्लेन के माध्यम से दिसंबर 2025 में हुआ जिसमे ठेकेदार उषा सिंह के द्वारा टापर के घर से 500 मीटर तक का नवनिर्माण कार्य नही किया गया जिससे टापर और उसके गांव वालों को आने जाने मे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही हर घर तक सड़क बना रही है लेकिन टापर के नाम की सड़क की मरम्मत टापर के घर तक नही की गई यह एक गंभीर सवाल उठ रहा है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए जल्द से जल्द टापर के घर तक सड़क का नवीनीकरण कराया जाए ताकि आने जाने वालों को कठिनाईयो का सामना ना करना पड़े।

गुजरात के 20 जिलों में 4 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित, आदिवासी जिलों में स्थिति गंभीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। गुजरात में बच्चों में कुपोषण को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार द्वारा दिए गए एक लिखित जवाब में यह खुलासा हुआ है कि गुजरात के 20 जिलों में कुल 4 लाख 3,051 बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं. कांग्रेस विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में, सरकार ने सदन में कुपोषित, कम वज़न वाले और बहुत कम वज़न वाले बच्चों के आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों के मुताबिक, कुपोषण की समस्या विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर दिखाई देती है. छोटा उदेपुर और नर्मदा जैसे आदिवासी जिलों में कुपोषित बच्चों की संख्या चिंताजनक है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, तापी में 8,848, नर्मदा में 8,881, छोटा उदेपुर में 32,644, पंचमहाल में 41,524, आनंद में 12,704, खेड़ा में 37,180, वलसाड में 14,974, डांग में 6,440, महिसागर में 15,676, दाहोद में 32,776, गिर सोमनाथ में 10,378, जूनागढ़ में 10,204, पाटन में 14,280, भरूच में 22,906, अहमदाबाद में 12,822, गांधीनगर में 12,934, बनासकांठा में 38,782, कच्छ में 23,093, अरावली में 12,824 और साबरकांठा में 33,176 बच्चों के कुपोषण से पीड़ित होने की सूचना मिली है।

बंगाल में चुनाव 23 व 29 अप्रैल को; असम, केरल व पुदुचेरी में 9, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 व 29 अप्रैल को होंगे, जबकि असम, केरल व पुदुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होंगे। सभी राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी घोषणा की। चुनाव आयोग ने कहा है कि 6 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन पांच राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में खत्म हो रहा है। इसलिए नए चुनाव ज़रूरी हैं। किन राज्यों में वोटिंग कब?असम- 9 अप्रैल,केरल- 9 अप्रैल,पुदुचेरी- 9 अप्रैल,तमिलनाडु- 23 अप्रैल तथा पश्चिम बंगाल- 23 और 29 अप्रैल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार कम चरणों में चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों ने 1-2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम की विधानसभा में 126 सीटें हैं जिनमें से 9 एससी और 19 सीटें एसटी के लिए रिज़र्व हैं।

केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 14 एससी और 2 सीटें एसटी के लिए रिज़र्व हैं। पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव हैं उनमें से 5 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 234 सीटें हैं और इनमें से 44 सीटें एससी व 2 एसटी के लिए रिज़र्व हैं। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से 68 सीटें एससी और 16 एसटी के लिए आरक्षित हैं। असम में हिमंता बिस्व सरमा की भाजपा सरकार है। यहां भी बहु-चरणीय चुनाव संभावित हैं। कार्यकाल 20 मई को खत्म हो रहा है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की डीएमके सरकार है। यहां एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। कार्यकाल 10 मई को खत्म होगा। केरल में पिनराई विजयन की एलडीएफ़ सरकार है। एक चरण में चुनाव की संभावना है। कार्यकाल 23 मई को ख़त्म हो रहा है। पुदुचेरी में एन. रंगासामी की एआईएनआरसी सरकार है। एक चरण में चुनाव संभव है। कार्यकाल 15 जून को खत्म होगा। एक बार तारीखें घोषित होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी पार्टियां प्रचार शुरू कर सकेंगी, लेकिन सरकारी घोषणाओं और फैसलों पर रोक लग जाएगी। चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है, ताकि नए सरकारें जून तक बन सकें।

प्रस्तावित आईपीओ के लिए एनएसई ने पूरी की सहयोगी कंपनियों के चयन की प्रक्रिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने आज अपने प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए मर्चेंट बैंकर, लॉ फर्म और अन्य सहयोगी कंपनियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह चयन प्रक्रिया एनएसई की आईपीओ समिति द्वारा तय किए गए फ्रेमवर्क और मूल्यांकन पद्धति के अनुसार की गई। पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से संपन्न हुई। चयनित 20 मर्चेंट बैंकर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड), मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, 360 वन डब्ल्यूएएम लिमिटेड, आनंद राठी एडवाइज़र्स लिमिटेड, डीएएम कैपिटल एडवाइज़र्स लिमिटेड, पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। चयनित आठ लॉ फर्म्स में सिरिल अमरचंद मंगलदास, खेतान एंड कंपनी, लैथम एंड वॉटकिन्स एलएलपी, सिडली ऑस्टिन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, एज़ेडबी एंड पार्टनर्स, एस एंड आर एसोसिएट्स, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी और ट्राइलिगल शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सहयोगी कंपनियों में एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मकरंद एम जोशी एंड कंपनी, मणियन एंड राव, आरबीएसए एडवाइज़र्स, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन लिमिटेड और रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया है। चुनी गई उपरोक्त सभी संस्थाएँ प्रस्तावित आईपीओ से जुड़े अलग-अलग कामों में एनएसई की मदद करेंगी। इसमें जरूरी कागज़ी प्रक्रिया, जाँच-पड़ताल, दस्तावेज़ तैयार करना, प्रचार से जुड़ी तैयारियाँ और आईपीओ की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जैसे कार्य शामिल होंगे, जो कि तय नियमों के अनुसार किए जाएँगे।

गर्मी में सेवा दे रहे लाइनमैन को किया गया सम्मानित

नैनी, प्रयागराज। भीषण गर्मी के बावजूद लगातार विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे लाइनमैन प्रमोद केसरवानी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय श्रीवास्तव ने उनका माल्यार्पण कर तथा अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया।संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भीषण गर्मी में भी लाइनमैन प्रमोद केसरवानी ऊँचे-ऊँचे विद्युत पोलों पर चढ़कर खराब लाइटों को ठीक करते हैं और क्षेत्र की जनता को रोशनी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसे समर्पित और कर्मठ कर्मचारियों का सम्मान करना समाज के लिए प्रेरणादायक है।इस अवसर पर क्षेत्र के सुपरवाइजर नईम खान, प्रभात जी, वरिष्ठ पार्षद मयंक यादव, सेक्टर संयोजक प्रदीप तिवारी, राज सिंह, सुधीर प्रजापति, नीरज शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी लाइनमैन प्रमोद केसरवानी का स्वागत कर उनके कार्यों की सराहना की। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने उनके सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं।

प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का मेडिकल परीक्षण

● 6 चिकित्सकों की टीम ने की जांच, वीडियोग्राफी भी कराई गई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में चर्चा में आये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का शनिवार को मेडिकल परीक्षण कराया गया. मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में सीएमओ के नेतृत्व में छह डॉक्टर के पैनल ने मेडिकल परीक्षण किया. इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर मोती लाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, प्रयागराज में विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया था. जिसके तहत शनिवार को चिकित्सालय में जीआरपी पुलिस की निगरानी में मेडिकल परीक्षण कराया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. पूरे चिकित्सीय परीक्षण की वीडियोग्राफी भी कराई गई. जारी पत्र के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड में फिजीशियन, डॉ. सीपी श्रीवास्तव, आर्थोसर्जन डॉ. रणधीर सिंह चौहान, नेत्र सर्जन, डॉ राम मिलन, ईएनटी सर्जन, डॉ. एके जायसवाल, सर्जन डॉ. आर्येंद्र सिंह, दंत सर्जन, डॉ. मिथलेश की टीम शामिल रही। मेडिकल बोर्ड की टीम ने नाक, दांत तथा आंख की चोटों सहित अन्य शारीरिक चोटों का परीक्षण किया और आवश्यक चिकित्सीय जांच की. इस दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड की निष्पक्ष जांच से घटना की वास्तविकता सामने आएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

'बहुजन समाज के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी कांग्रेस', कांशीराम की जयंती पर बोले राहुल गांधी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और समाज सुधारक कांशीराम की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज की भागीदारी, सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए पहले भी खड़ी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'बहुजन नायक कांशीराम की जयंती पर उन्हें सादर नमन।

गरीबों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनका अथक संघर्ष और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका मानना था संविधान ही दलितों, पिछड़ों और वंचितों की असली ताकत है। ' राहुल गांधी ने लिखा, 'संविधान आज खतरे में है। बाबा साहेब के संविधान की शपथ ले कर सत्ता में बैठने वाले ही उसको कमजोर करने पर तुले हैं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं, तब तक न्याय संभव नहीं, कांशीराम की विरासत यही कहती है। सामाजिक न्याय का यह सपना अधूरा नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज की भागीदारी, सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए पहले भी खड़ी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ' इससे पहले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया, 'महान समाज सुधारक कांशीराम ने दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों को संगठित कर उन्हें भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया।

सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ' वहीं, आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा, 'सामाजिक न्याय के प्रणेता, वंचितों के राजनीतिक एकीकरण व उत्थान के पुरोधा, हाशिए के समूहों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले लोक समता के पैरोकार, महान समाज सुधारक कांशीराम की जयंती पर कोटि-कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने जो राह उत्पीड़ित व शोषित वर्गों को दिखाई, उसी पर चल कर ही देश में समान विकास और समता स्थापित हो सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य विकल्प नहीं, जीवन के लिए अनिवार्य है : डॉ. मालविका राव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रो. धीरेन्द्र वर्मा शताब्दी सभागार में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था - 'छात्र जीवन में अवसादः कारण और उपचार' और वक्ता सुपरिचित वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. मालविका राव थीं। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रो. लालसा यादव ने मुख्य वक्ता का स्वागत करते हुए की। इसके बाद कार्यक्रम का संचालन कर रही शोधार्थी रिया ने डॉ. मालविका राव का परिचय देते हुए बताया कि डॉ. मालविका राव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही मनोविज्ञान में परास्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उन्हें 2014 में पी.सी. दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद, 2022 में उन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सच्ची दस्तक महाराष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया, और 2023 में पूनम संत महिला एवं विकास समिति ने उन्हें एक सोशल वर्कर के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इसके बाद कार्यक्रम के संयोजक प्रो. संतोष भदौरिया ने समाज में बढ़ते तनाव और अवसाद के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसका एक मुख्य कारण 90 के दशक के बाद वित्तीय पूंजीवाद के आगमन से सामाजिक संबंधों में आए मूलभूत परिवर्तन हैं। प्रो. भदौरिया ने इस बात पर बल दिया कि मनोचिकित्सक से सहायता लेने के संबंध में समाज में एक गलत धारणा व्याप्त है कि ऐसे व्यक्ति सामान्य नहीं होते, जबकि तनाव और अवसाद कई प्रकार के होते हैं और किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक दबावों, जैसे रिश्तेदारों के अनपेक्षित प्रश्न और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न अकेलेपन को भी तनाव के प्रमुख कारणों में गिनाया। प्रो. भदौरिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिंदी विभाग में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाठ्यक्रमों की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हैं और समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। अंत में, उन्होंने स्वस्थ मस्तिष्क के लिए सकारात्मक सोच और नवाचार को अनिवार्य बताया और डॉ. मालविका राव की टीम का हार्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ. मालविका राव ने श्रोताओं को मानसिक स्वास्थ्य के विषय में अपनी अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य चिंतन, बोध, अधिगम और भावनात्मक संतुलन का एक समाहित स्वरूप है। उन्होंने इस बात पर दृढ़तापूर्वक बल दिया कि मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन एक-दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, और किसी एक में भी उत्पन्न असंतुलन दूसरे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। डॉ. मालविका राव के अनुसार, चिंता, तनाव और अवसाद जैसी मानसिक व्याधियाँ सामान्य हैं, तथापि लोग प्रायः इनके लक्षणों को पहचानने अथवा यह स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं कि कोई भी इनसे प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने नींद में व्यवधान, सामाजिक अलगाव और अत्यधिक चिंतन जैसे चेतावनी संकेतों पर विशेष बल दिया। डॉ. राव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि छात्रगण प्रायः अध्ययन के दौरान एकाग्रता में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अत्यधिक चिंतन और काल्पनिक दुनिया में विलीन हो जाते हैं। उन्होंने समझाया कि यह स्थिति उन्हें वास्तविक धरातल से विमुख करती है और परीक्षा के तनाव व घबराहट का कारक बन सकती है। डॉ. मालविका राव ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि अभिभावक और शिक्षक प्रायः इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने में विफल रहते हैं और उन्हें सामान्य परिघटना मानकर अनदेखा कर देते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नकारात्मक विचारों, भावनात्मक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन और मनोदशा में तीव्र परिवर्तनों को जन्म दे सकती है। डॉ. मालविका राव ने यह भी स्पष्ट किया कि मोबाइल की आसक्ति भी सामाजिक अलगाव का एक रूप है, क्योंकि यह व्यक्तियों को वास्तविक जगत से पृथक कर एक आभासी संसार में धकेल देती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होते हैं, तो वे स्वयं को दुनिया से विलग कर लेते हैं और अपनी असफलताओं पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। व्याख्यान के बाद डॉ. मालविका राव ने मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित विद्यार्थियों के जिज्ञासाओं और उनके प्रश्नों का जवाब दिया। कार्यक्रम के सफल समापन पर, शोधार्थी सृष्टि ने सभी उपस्थितजनों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में प्रो. भूरेलाल, प्रो. राकेश सिंह, डॉ. सूर्यनारायण, डॉ. सीमा जैन, डॉ. संतोष कुमार सिंह, डॉ. बिजय रविदास, संजय पाण्डेय, श्वेता, अभिषेक, महताब, जया, रिया, सोमदेव, मनीष तथा बड़ी संख्या में शोधार्थियों और छात्रों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को अज्ञात बाइक सवारों ने मारी टक्कर,मौत

पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया

नैनी, प्रयागराज। औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके में शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को अज्ञात बाइक सवारों ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार करछना थाना क्षेत्र के ग्राम अन्तहिया, खाँई निवासी भुवनेश्वर प्रसाद पाण्डेय (पुत्र स्वर्गीय चन्द्रशेखर प्रसाद पाण्डेय) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी भयाहू अंजू पाण्डेय (लगभग 50 वर्ष) सेंट जोसफ स्कूल के पीछे स्थित अपने आवास में रहती थीं। शनिवार 14 मार्च 2026 की सुबह करीब 6 बजे वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थीं। इसी दौरान दो अज्ञात बाइक सवारों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए।घटना के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि दो बाइक सवारों ने ही महिला को टक्कर मारी थी, लेकिन उनका नाम-पता किसी को मालूम नहीं है।परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मार्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।